Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069 COSMOS Impact Factor: 4.964, Volume 06, No. 01, January-March, 2020, pp. 173-176

भारत के आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका

हेमलता शाक्य*

सार

भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। इसमें आधुनिक बैंकिंग सेवाओं का इतिहास 200 वर्ष पुराना हैं । भारत के आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज्य में हुई हैं । यहां प्रारंभ में बैंकों की शाखाएं और उनका कारोबार वाणिज्य केंद्रों तक ही सीमित होता था। स्वतंत्रा के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक का दर्जा बरकरार रखने के लिये उसे बैंकों का बैंक घोषित किया गया। सभी प्रकार की मौद्रिक नीतियों को तय करने और उसे अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लागू कराने का दायित्व भी उसे सौंपा गया। इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की नियंत्रण तथा नियम शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। बैंकों ने सदियों से अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित किया हैं। बैंकिंग उद्योग व्यापारों के साथ या उपभोक्ताओं के लिए नहीं वाणिज्यक उधार आज एक बहुत ही गहन विधि हैं । विभिन्न प्रकार की आवश्यकता और देश के विकास में बैंकों की भूमिका हैं। जो विभिन्न सेवाओं और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करते हैं। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बैंक की व्यवस्था का अध्ययन महत्वपूर्ण स्थान होता हैं। बैंक मुद्रा बाजार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। पूंजी निर्माण व्यापार उद्योग एवं कृषि के अर्थ प्रबंधन तथा देश की आर्थिक सामाजिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं । किसी भी देश का विकास पूंजी निर्माण की दर पर निर्भर करता हैं।

कुंजी शब्दः *पूंजी निर्माण बैंक मुद्रा।*

परिचय

भारत में बैंक व्यवस्था

आज विश्व के प्रायः सभी विकासशील देश आर्थिक नियोजन के आधार पर अपना विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। जिसकी उपलब्धि केवल निजी क्षेत्र के द्वारा ही नहीं की जाती बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों का इसमें विशेष योगदान रहता है। किसी भी प्रकार के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के अनेक कार्यक्रमों में जोखिम की मात्रा भी अधिक होती है क्योंकि धन लगा देने के बाद यह आवश्यक नहीं है कि उससे शीघ्र ही पर्याप्त लाभ मिल जाये। निजी क्षेत्र उन्हीं उपक्रमों में विनियोग करना चाहता है जो शीघ्र ही अधिक लाभ दे सकते है और जिनमें जोखिम की मात्रा भी कम होती है, किंतु यह देश के सर्वागीण आर्थिक विकास में योगदान नहीं देता है। सार्वजनिक क्षेत्र ही एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जो कि ऐसे उपक्रमों का विकास करता है जो भले ही देर से लाभ दें पर देश के विकास में योगदान कर सकें।

* सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग, शासकीय गीतांजली कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, भोपाल, म.प्र.।.

सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक सुरक्षा सम्बन्धी उपक्रम है जिस पर व्यक्ति भरोसा कर सकता है और पूंजी को सुरक्षित रख सकें। यह उपक्रम राष्ट्रीय तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण होते है। इन उपक्रमों में जोखिम की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये इन पर भरोसा को ध्यान में रखते हुये इन पर भरोसा करके लोग जोखिम मुक्त रहते है। इन सार्वजनिक उपक्रमों के आने से लोगों का सरकार पर विश्वास हो गया है। जिससे वह अपनी पूंजी इन बैंकों को सौंपे और सुरक्षित महसूस करें। आजकल बैंक सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तृत है।

सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों का मुख्य उद्देश्य लोगों तक सेवाओं को पहुँचाना और उनके एवं देश के आर्थिक विकास में योगदान देना है। जिससे पूर्ण रूप से देश का आर्थिक विकास किया जा सके। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय बैंकिग उद्योग में कुछ अग्रिमों का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले चार–पांच दशकों मे जबरदस्त वृद्धि दिखाई है। भारत के हमारे अपने बैंकिग क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या सिंतबर 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंक है– 19 राष्ट्रीकृत बैंक, आई.डी.बी.आई. बैंक और भारतीय स्टेट बैंक है। 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ;त्नतंस त्मंहपवदंस ठंदाद्ध हैं जो इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक के स्वामित्व में है। ये बैंक किसी विशेष राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के कुछ जिलों में ग्रामीण बैंकिंग पर केन्द्रित है। इन बैंकों में सरकार की 51ः से अधिक इक्विटी हिस्सेदारी है, इसलिए इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा जाता है।

बैंक की विशेषताएंः

बैंक वह संस्था है जो–

- जनता से जमा के रूप में धन स्वीकार करती है।
- जनता को जमा धन वापस निकालने की सुविधा देती है।
- अपने नाम के आगे, बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोग करती है।
- सामान्य सेवाएं प्रदान करती है।
- बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित अन्य कार्य करती है।

बैंक के कार्य

भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के अनुसार बैंक के निम्न दो मुख्य कार्य है–

- जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करना, तथा
- धन उधार देना तथा मांग पर वापस निकलने की सुविधा देना।

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था

परिवर्तन एवं विकास विश्व की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सभ्यता के विकास के साथ–साथ आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति एवं विकास होता जा रहा है। व्यावसयिक एवं औद्योगिक प्रगति के लिये वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हमें बैंकों पर निर्भर होना पड़ता है। समाज एवं उद्योग की वित्तीय आवश्कताओं में भी निरंतर परिवर्तन एवं संवर्द्धन होता जा रहा है, अतः आज बैंक संगठन का वह स्वरूप नहीं है, जो प्राचीन काल में था। प्राचीन काल में बैंकिंग का कार्य एक व्यक्ति या फर्म करती थी, जिन्हें साहूकार या महाजन कहा जाता था। इस प्रकार, निजी बैंकों की पूंजी, साधन एवं क्षेत्र अति सीमित थे और ब्याज दर काफी ऊंची होती थी। अतः आधुनिक समय में पाश्चात्य प्रणाली पर संयुक्त स्कन्ध कंपनियों के रूप में बैंक स्थपित किए गए है, जिनके पास वृहत पूंजी साधन होते है।

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण बैंकिंग संस्थानों को सम्मिलित किया जा सकता है, जो कि पूरे भारत में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे है। ये संस्थान एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न वर्गो को उनकी आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहें है। यह एक बड़ा विस्तृत, जटिल एवं सघन संगठन है, जो कि देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें संगठित एवं असंगठित निजी एवं सार्वजनिक, देशी एवं विदेशी, ग्रामीण एवं शहरी आधुनिक एवं परंपरागत सभी प्रकार के रूप देखने को मिलते हे। वास्तव में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था यहां की सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्था की भांति अपनी विविधताओं से परिपूर्ण है।

भारतीय बैंकों की मौद्रिक नीति

अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु नये विनियोगों को प्रोत्साहान दिया जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में आय मुद्रा में लिखी जाती है और मुद्रा को अंको में ही लिखा जाता है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक हर दूसरे महीने मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, इस पर आर.बी.आई. की पैनी नजर होती है एवं इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए नीतिगत ब्याज दरें घटाने या बढ़ाने का फैसला किया जाता है, यह फैसला केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एम.पी.सी.) लेती है और इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है। मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया है, जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है।

वर्ष 1980 की मौद्रिक नीति में सामान्य साख प्रसार की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया गया। 1990के दशक में उदारीकृत अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। भारत में मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जा सकें। भारत की मौद्रिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य है।

- **मूल्य स्थिरता–** मूल्य स्थिरता की आवश्यकता आर्थिक विकास के साथ–साथ मूल्यों के बढ़ने की गति के ऊपर विराम लगाने के लिए अत्यंत जरूरी होती है, इस रणनीति के तहत उन पर्यायवरणीय तथ्यों को बढ़ावा देना है जो न केवल वस्तुकला के विकास के लिए जरूरी हो बल्कि उनके विकास की गति को भी बनाये रख सकें। साथ ही मूल्य वृद्धि के ताक्रिक महत्व को समझ सकें।
- **बैंक के ऋणों की बढ़ोत्तरी पर नियंत्रण बना रहे–** भारतीय रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यो में से एक, उत्पादन को प्रभावित किए बिना उधार पर दिए जाने वाले ऋणों को कम करना है। साथ ही मौसमी आवश्यकताओं और उत्पादों को ध्यान में रखते हुए बैंक ऋण और मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रित विकास करना है।
- **स्थिर निवेश का संवर्धन–** गैर जरूरी और निश्चित निवेश को सीमित करके निवेश की उत्पादकता को बढ़ाने के लिये योजना बनाना है।
- **माल की पूर्ति पर प्रतिबंध–** उत्पादों की भरमार और उनकी अधिकता एवं सामानों के अधिक मात्रा में आपूर्ति के कारण उत्पादक इकाइयां बीमार हो रही है। इसी समस्या के संदर्भ में केन्द्रीय मौद्रिक प्राधिकरण ने सामानों के प्रवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। इस रणनीति के तहत कई कार्य, किये गयें है, जैसे सामानों के स्टॉक होने से बचना और संगठन के अंतर्गत सुस्त मुद्रा को रोकना।
- **निर्यात के संवर्धन और खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया का संचालन–** मौद्रिक नीति निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार की सुविधा संदर्भ में विशेष जोर देता है यह मौद्रिक नीति का एक स्वनियंत्रित उपाय है।
- **ऋण का वांछित वितरण–** मौद्रिक प्राधिकरण छोटे उधारकर्ताओं और प्राथमिक क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के आवंटन से संबंधित फैसलों पर नियंत्रण करता है।
- **ऋण का समान वितरण–** रिजर्व बैंक का नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को समान लाभ का अवसर उपलब्ध कराया जाता है।
- **दक्षता को बढ़ावा देना–** यह वित्तीय प्रणाली के प्रभाव को बढ़ावा देता है। साथ ही संरचनात्मक परिवर्तनों, जैसे ऋण वितरण प्रणाली में आसान परिचालन, ब्याज दरों के वृद्धि पर नियंत्रण आदि स्थापित करता है। इसके अलावा मुद्रा के संदर्भ में बाजार में नए–नए मानदंडो को भी स्थापित करता है।
- **कठोरता को कम करना–** यह अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल और विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है।

शोध की आवश्यकता

अनुसंधान सुधार और विकास की जननी है अनुसंधान के समय पुरानी शोध कार्य की ध्यान में लेना भी आवश्यक होता हैं, अन्यथा हमारे अनुसंधान में व्यर्थ में समय और संसाधनो की बर्बादी हो सकती है यदि इसी प्रकार का अनुसंधान पहले किया जा चुका है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी या उसे नवीन तरीके से किया जाना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान की श्रंखला में कुछ अधूरापन भी रह सकता हैं इसीलिए हमारा अनुसंधान पिछले शोध को लेते हुए चरणबद्ध क्रम में होते है।

भारत में बैंकों की स्थापना एवं विकासः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बैंक शब्द की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रमाण है, प्रथम प्रमाण के अनुसार बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द BANCO या BANQUE से हुई है, जबकि द्वितीय प्रमाण के अनुसार बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द BANCK से हुई है जिसका अर्थ है संयुक्त कोष, अर्थात उस समय लोग बेंच पर बैठकर मुद्रा का लेन–देन करते थे, इसलिये बैंक 'बेंच' का एक विकसित रूप भी माना जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

~ Bhattacharya, K. M., and Agarwal, O.P. (2006). Basics of Banking and Finance, Himalaya Publishing House First Edition, Mumbai.

~ Joshy, V., and Little, J.M.D. (1998). India's Economic Reforms: 1991-2001, Oxford University Press, New Delhi.

~ www.indianeconomic.com.

❑❑❑